G20 ITALIA 2·0·2·1
BRICS INDIA 2021

जी20 और ब्रिक्स संरचना में आवश्यक सुधार

HEINRICH BÖLL STIFTUNG INDIA

VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

जी–20 और ब्रिक्स संरचना में आवश्यक सुधार

लेखकः वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

अक्टूबर 2022

कॉपीराइट (सी) वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
प्रकाशक की स्वीकृति के साथ इस लेख की विषय वस्तु को संपूर्ण या भागों में पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रकाशनः
वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
वाणी हाउस, 7, पीएसपी पॉकेट,
सेक्टर –8, द्वारका, नई दिल्ली –110 077
फोनः 91-11-49148610, 40391661, 40391663
ईमेलः info@vaniindia.org
वेबसाइटः www.vaniindia.org

@TeamVANI @vani_info @VANI India @VANI Perspective

डिज़ाइन : **शेड्स**

प्रस्तावना

वैश्विक महामारी और बदलते पारिस्थितिक तंत्र में अपने अस्तित्व की लड़ाई के बाद, दुनिया अपनी सुरक्षा और शांति में कई प्रकार के संकटो का सामना कर रही है। दुनिया भर में भू–राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता तथा अन्य कई समस्याओ ने अनिश्चितता की स्थिति के साथ वैश्विक संकट को प्रकट किया है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, डिजिटल डिस्कनेक्ट (वियोजन) आदि की समस्या पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। इस नए और बदलते परिवेश में जी–20 और ब्रिक्स जैसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मंचों से पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा की जाती है। इन मंचों को इन अपेक्षाओं और उनके आवश्यक उत्तरदायित्वों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए संस्थागत कार्यप्रणाली और वित्तीय सुधारों पर कार्य करना अनिवार्य है।

कोविड के बाद की दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जी–20 और ब्रिक्स पर लगातार उच्च आशंकाए लगायी जा रही है, क्रमशः आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और शांति तथा सहयोग सुनिश्चित करने की उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। हालाँकि, तेजी से बदलते पारिस्थितिक तंत्र जैसे रूस–यूक्रेन युद्ध, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन आदि के विनाशकारी प्रभावों द्वारा इन मंचो की विश्वसनीयता तब तक सुनिश्चित नहीं की जा सकती, जब तक कि वे इस तरह से तैयार न हों कि वे सदस्य राष्ट्रों के एक संयुक्त एजेंडा को प्रस्तुत करे। इसलिए, यह महत्वपूण् र् है कि सदस्य राष्ट्र इन दोनों अंतरराष्ट्रीय समूहों में आवश्यक सुधार लाने और आवश्यक प्रगति के लिए विचार–विमर्श को आगे बढ़ाएं।

अंत में, मैं इस रिपोर्ट को तैयार करने में हेनरिक बोएल फाउंडेशन के योगदान को स्वीकार करता हूँ। मैं डॉ. पल्लवी रेखी, कार्यक्रम अधिकारी, वाणी को भी इस रिपोर्ट पर शोध करने और उसे तैयार करने के लिए धन्यवाद करता हूँ।
एकता के साथ,

हर्ष जेटली,
सीईओ, वाणी

G20
ITALIA
2·0·2·1

BRICS
INDIA 2021

विषय–सूची

20 का समूह 6

उत्पत्ति और विकास 6

संगठनात्मक संरचना 7

गैर–सदस्यों द्वारा भागीदारी 7

जी–20 शिखर सम्मेलन का प्रक्षेप पथ 7

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) 8

उत्पत्ति और महत्व: ब्रिक से ब्रिक्स तक 8

ब्रिक्स सदस्य 8

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का प्रक्षेप पथ 9

जी–20 का विश्लेषण 9

अन्य मंचों के मुकाबले जी–20 के लाभ 10

जी–20 की सीमाएं 11

जी 20 के वर्षों के प्रदर्शन का आकलन 12

ब्रिक्स का विश्लेषण 13

न्यू डेवलपमेंट बैंक 15

कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट 15

भविष्य कैसा होगा? 16

शेष प्रासंगिक 17

संदर्भ 19

परिचय

20 का समूह

जी–20 समूह में दुनिया की बीस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय संघ के साथ शामिल हैं। जी–20 सदस्य वर्तमान में विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 80% से अधिक, वैश्विक व्यापार का 75% और वैश्विक जनसंख्या का 60% हिस्सा हैं।

उत्पत्ति और विकास

वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में जी–20 की स्थापना की गई थी। जी–20 को बाद में राज्य / सरकार के प्रमुखों के स्तर पर विकसित किया गया था और इसे ''अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच'' घोषित किया गया था। 2011 के बाद से, जी–20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक रोटेटिंग प्रेसीडेंसी (क्रमिक अध्यक्षता) के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। जी–20 ने शुरू में व्यापक आर्थिक नीति पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन बाद में इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, दीर्घकालीन विकास, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोधी आदि को शामिल करके अपने दायरे का विस्तार किया है।

संगठनात्मक संरचना

जी 20 का कोई अधिकारपत्र या सचिवालय नहीं है। इसके अध्यक्ष, पहले और बाद में अध्यक्षता प्राप्त करने वाले देशों की सहायता से (ट्रोइका), प्रत्येक वर्ष के शिखर सम्मेलन के एजेंडे को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होते है। जी–20 प्रक्रिया का नेतृत्व सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी दूत होते हैं। शेरपा, वर्ष के दौरान बातचीत करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा मदों पर चर्चा करते हैं और जी–20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं। जी–20 का काम दो भागो में बांटा गया है: वित्तीय कार्य और शेरपा के कार्य। दोनों भागो में, विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह हैं जिनमें सदस्यों के प्रासंगिक मंत्रालयों के साथ–साथ आमंत्रित/अतिथि देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कार्यकारी समूह प्रत्येक प्रेसीडेंसी (अध्यक्षता) के पूरे कार्यकाल के दौरान नियमित रूप से मिलते हैं। एजेंडा वर्तमान आर्थिक विकास के साथ–साथ पिछले वर्षों में स्वीकृत कार्यों और लक्ष्यों से भी प्रभावित होता है। संस्थागत निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जी 20 में एक बहु–वर्षीय जनादेश है।

गैर–सदस्यों द्वारा भागीदारी

जी–20 में कुछ गैर–सदस्य देशों के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित करने की परंपरा रही है। स्पेन को छोड़कर, जो एक स्थायी अतिथि है, ये देश साल–दर–साल बदलते रहते हैं। जी–20 प्रक्रिया में नियमित भागीदार इंटरनेशनल मॉनेटरी फण्ड (आईएमएफ), वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस (यूएन), आर्गेनाइजेशन फॉर इकनोमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी), वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ), इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन (आईएलओ) और फाइनेंसियल स्टेबिलिटी बोर्ड (एफएसबी) के साथ साथ क्षेत्रीय संगठनों की अध्यक्षता करने वाले देश जैसे कि ऐसिअन (एएसईएएन), अफ्रीकन यूनियन और विकास कार्यक्रम नेपाड़ (एनईपीएडी) शामिल हैं। मौजूदा अध्यक्ष जी–20 बैठकों और शिखर सम्मेलनों के लिए अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित कर सकते हैं।[1]

जी–20 शिखर सम्मेलन का प्रक्षेप पथ

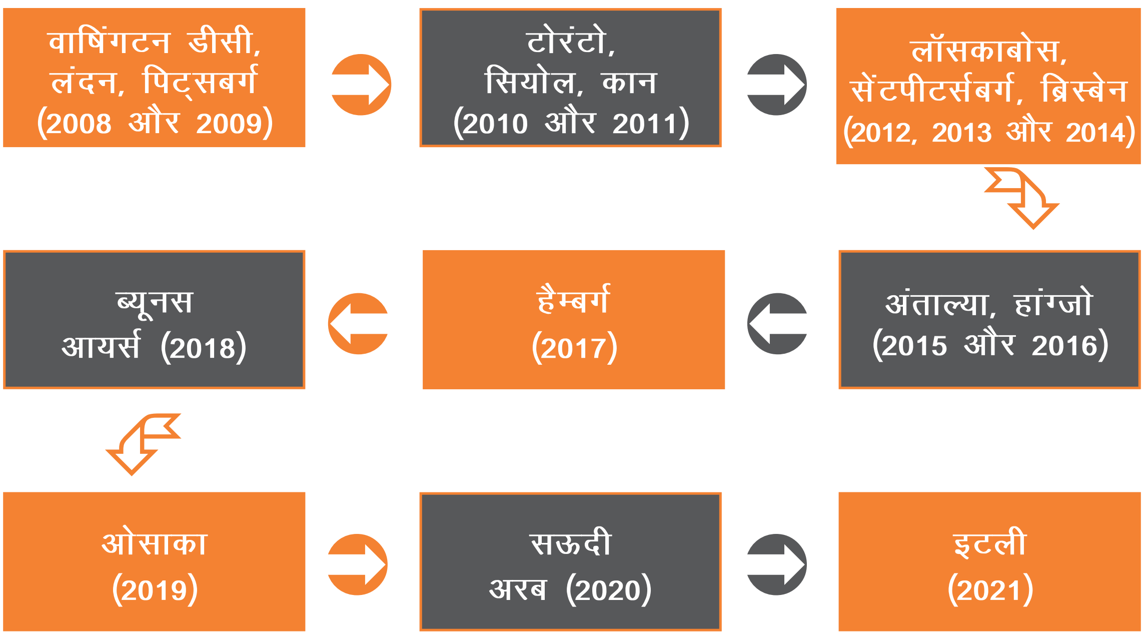

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका)

ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की पांच उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स द्वारा प्रस्तावित दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में से उभरते इन पांच देशों को वैश्विक शक्ति के केंद्र के रूप में देखा जाने लगा। 2008–2009 के वैश्विक वित्तीय संकट (ग्लोबल फाइनेंसियल क्राइसिस–जीएफसी) के साथ, इस समूह का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मामलों के संबंध में सहयोग, नीति समन्वय और राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देना था। हालाँकि, अपनी स्थापना के बाद से, ब्रिक्स ने अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है, विशेष रूप से समूह की नियमित बैठकें आयोजित करने, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में समन्वय की स्थिति और अपने सदस्यों के बीच बहु–क्षेत्रीय सहयोग के लिए एजेंडा का विकास करने के लिए। 2009 में समूह को राज्य के प्रमुखों के पहले शिखर सम्मेलन के साथ संघटित किया गया था। इसके बाद, समूह वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हर साल एक बैठक करता है।

उत्पत्ति और महत्वः ब्रिक से ब्रिक्स तक

ब्रिक को पहली बार गोल्डमैन सैक्स के जिम ओ 'नील द्वारा वर्ष 2001 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, इनके प्रस्तुतीकरण के समय यह अनुमान लगाया गया था कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कहीं अधिक अधिग्रहण करेंगी और अगले 50 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगी। हालांकि, 2006 में जी 8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के बाद पहली बार समूह की बैठक हुई। 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के दौरान यह समूह ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के संघटित हुआ। इसके बाद, जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के लिए समूह का विस्तार हुआ। इसके पश्चात, दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में सान्या, चीन में ब्रिक्स के तीसरे शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

ब्रिक्स सदस्य

ब्रिक्स की ये पांच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं मिलकर दुनिया की 40% से अधिक आबादी, विश्व सकल घरेलू उत्पाद के 30% से अधिक और विश्व व्यापार में 17% की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करती हैं। समूह अनिवार्य रूप से आपसी हितों के आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में शुरू हुआ था। हालांकि, महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को शामिल करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स के एजेंडे के दायरे में काफी विस्तार हुआ है। ब्रिक्स सहयोग दो स्तंभों पर आधारित है दृ वित्त, व्यापार, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि, संचार, श्रम आदि पर नेताओं एवं मंत्रियों से आपसी हित के मुद्दों पर परामर्श और कई क्षेत्रों में कार्यकारी समूहों/वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों के माध्यम से व्यावहारिक सहयोग द्वारा।

विश्व व्यापार संगठन (वर्ल्ड ट्रेड सेंटर –डब्ल्यूटीओ) के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स की भागीदारी 2001 और 2011 के बीच 8% से बढ़कर 16% हो गई है। इन वर्षों में, उनके कुल निर्यात में 500% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में कुल वैश्विक निर्यात में 195% की वृद्धि हुई है। 2002 और 2012 के बीच, इंट्रा–ब्रिक्स व्यापार 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 276 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि 2010 और 2012 के बीच, ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 29% बढ़कर 4.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 6.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। (2)

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का प्रक्षेप पथ

येकातेरिनबर्ग, रूस (2009) → ब्रासीलिया, ब्राजील (2010) → सान्या, चीन (2011) → नई दिल्ली, भारत (2012) → डरबन, दक्षिण अफ्रीका (2013) → फोर्टालेजा, ब्राजील (2014) → ऊफा, रूस (2015) → भारत (2016) → शामीन, चीन (2017) → दक्षिण अफ्रीका (2018) → ब्राजील (2019) → रूस (2020) → भारत (2021)

जी–20 का विश्लेषण

जी–20 को अब कई साल हो गए हैं। 1997–1998 में दुनिया जिस आर्थिक संकट से गुजरी, उसके बाद 1999 में इसने वित्त मंत्रियों की अपनी पहली बैठक बुलाई। 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा आयोजित एक बैठक, जिसमे सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकसित देशों में विचार विमर्श का जन्म हुआ, जो आर्थिक गिरावट और सर्वोपरि महत्व के विषयों पर विचार विमर्श, जैसे वित्तीय संकट से उभरना, बैंकिंग नियमों को सरल बनाना और विश्व व्यापार को किकस्टार्ट करना आदि सम्मिलित थे।

हालाँकि, जी–20 विविध परिस्थितियों वाले बीस देशों का एक समूह है, जो अपने देश–विशिष्ट मुद्दों से जूंझते हैं, कुछ विकसित हैं जबकि अन्य उस सूची में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जी–20 द्वारा अपेक्षाओं में अंतर और वैश्विक एजेंडा के बारे में विविध विचार प्रक्रियाएं सदस्यों के बीच संघर्ष को जन्म देता है। जी–20 सदस्य देशों के विचारो में मतभेदों को कम करने और लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जी–20 अपनी संकल्पना के बाद, प्रारंभिक वर्षों में अपनी भूमिका को बनाए रखने में काफी सफल रहा। दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों को बहाल करने, वित्तीय नियमों को पुनः स्थापित करने, मुक्त व्यापार प्रथाओं को सक्षम करने और वित्तीय संकट को दूर करने के लिए ऋण देने की क्षमता का विस्तार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध था।

अपने प्रारंभिक वर्षों में, जी–20 अपने जनादेश के अनुसार प्रगति कर रहा था और अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिसके लिए इसे बनाया गया था, चाहे वह आर्थिक हानि को रोकने या केवल विकसित राष्ट्रों को शामिल करने की नीति को बदलना हो, जी–20 बड़े पैमाने पर बोर्ड में सुधार करने और आईएमएफ के वोटिंग अधिकारों को पुनः स्थापित करने में भी सफल रहा, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में, तथा अपने संसाधनों में वृद्धि प्राप्त की। हालांकि, जैसे ही वैश्विक स्थिति में सुधार शुरू हुआ, संयुक्त रूप से कार्रवाई करने की प्रेरणा कम हो गई और परिणाम स्वरूप, जी–20 की भूमिका संदिग्ध हो गई। वर्षों से जी–20 का एजेंडा, अपनी प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय तत्कालीन संकट से प्रभावित रहा है।

इन चुनौतियों के रूप में, जी 20 फोरम का प्रभाव और भूमिका बहस का मुद्दा बन गया है। ऐसी परिस्थितियों ने इस मंच के अस्तित्व और महत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या जी–20 विश्व स्तर पर दीर्घकालीन विकास के अपने वादे को पूरा कर पाएगा? क्या यह बेहतर आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार कर पाएगा? इन सवालों के उन्मूलन के लिए, जी–20 द्वारा कुछ चुनौतियों को हल करने की आवश्यकता है। जी 20 को अपने लाभ पर पुनर्विचार करने, यथार्थवादी और बुद्धिमान लक्ष्यों से जुड़े रहने, निर्णय प्रक्रिया में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने और प्रत्येक स्थिति पर अधिक स्पष्टता के साथ स्वयं को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। विशाल अर्थव्यवस्थाएं, जो जी 20 की सदस्य हैं, ऐसे ढांचे को विकसित करने में मदद कर सकती हैं।

अन्य मंचों के मुकाबले जी–20 के लाभ

जी–20 को एक लचीले मंच के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका कोई बाध्य समझौता नहीं है, विचार विमर्श सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है, विवरण केवल आगे के मार्ग और मंच के उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। यह समूह विश्व हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और एक संचालन समिति की तरह सुझाव प्रदान करता है। यह परियोजनाओं के आरोपण के बजाय रणनीतिक समन्वय के लिए एक निकाय के रूप में कार्य करता है। जी–20 का लचीलापन और व्यावहारिकता उसे अन्य समान मंचों के मुकाबले बेहतर साबित करती है। यह कानूनी निहितार्थों और तेजी से बदलते परिवेश की चिंता किए बिना आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि जी–20 जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने में सफल नहीं रहा है। बीजारोपण स्तर पर पहले से स्थापित बहुपक्षीय संस्थान जी–20 के उनके क्षेत्र में अतिक्रमण से प्रसन्न नहीं हैं। ये छोटे संस्थान जी–20 की तुलना में कहीं अधिक विशेषज्ञता प्रदर्शित करते हैं। इनमें से प्रत्येक निकाय की सीमाओं को समझना और स्वीकार करना अनिवार्य है। प्रत्येक निकाय की एक निर्धारित भूमिका और उद्देश्य हैं, जिसके लिए उसे स्थापित और संरचित किया गया था। इसलिए, इनका आधार सुनिश्चित रहना चाहिए और इन मंचों के एजेंडे को वर्तमान विश्व प्रभुत्व से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ताकि उनकी विश्वसनीयता बनी रहे। इसी प्रकार, 1997–98 के दौरान दुनिया में आए आर्थिक संकट पर विचार विमर्श करने के लिए बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के बीच समन्वय के लिए जी–20 का गठन किया गया था। यह मूल रूप से, वित्तीय संकट के प्रभावों को दूर करने के लिए एक रणनीति बनाने और सरकार को नीतिगत स्तरों पर उचित कार्रवाई करने के लिए सुझाव प्रदान करने के लिए था। जी–20 की कल्पना कभी भी निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में नहीं की गई थी। इसलिए, जी–20 के विषय में चिंताएं प्रेस को अवसर प्रदान करती हैं, जो कि प्रासंगिक हैं।

दूसरे शब्दों में, दुनिया भर के राष्ट्रों को जी–20 द्वारा विकसित रणनीति को देखना चाहिए और इनके रणनीतिक सुझावों को जमीनी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसे छोटे संस्थानों की ओर परिवर्तित करना चाहिए। संचालन समिति या समन्वय के लिए एक ऐसे निकाय को डिजाइन किया गया है।

जी–20 की सीमाएं

किसी भी अन्य बहुपक्षीय मंच की तरह ही, जी–20 की भी कुछ सीमाएँ हैं। इस मंच से अपेक्षाएं उसकी सीमाओं और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए। यहाँ ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जी–20 के सभी सदस्य भिन्न हैं। उनके हित, आर्थिक स्थितियां भी भिन्न हैं, प्रत्येक सदस्य के लिए प्रगति का एक अलग अर्थ हो सकता है। वैश्विक असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए जी–20 का आग्रह इस चुनौती का एक उदाहरण है। इसलिए, सदस्यों के बीच उनकी रुचियों और आवश्यकताओं के आधार पर असहमति हो सकती है। दुर्भाग्य से, आज तक, जी–20 इन मतभेदों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक भी दिशानिर्देश विकसित करने और स्पश्ट लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम नहीं हो पाया है। यह भी देखा गया है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच असंतुलन को हल करना हमेशा इस समूह के एजेंडे के केंद्र में रखा गया है, वास्तविक आवश्यक घरेलू सुधारों की अनदेखी करके उन्हें वैश्विक चुनौती के रूप में प्रदर्शित किया है। हालाँकि, इन असंतुलनों को संतुलित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वे उनके हित में न हों – चाहे वह आंतरिक खपत के लिए अपनी घरेलू उपज को बढ़ावा देने वाला चीन हो या अंत से बचने के लिए अपने घाटे और ऋण को कम करने, अमेरिकी समृद्धि और नेतृत्व के लिए नाटकीय कदम उठाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका हो। विकसित राष्ट्र अपनी स्थिति और सत्ता को सिर्फ इसलिए दांव पर नहीं लगा सकते कि जी–20 ऐसा करने का सुझाव देता है। इसलिए, जी–20 को घरेलू सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक समाधान खोजना होगा अथवा असंतुलन को कम करने के अपने लक्ष्य को भूलना होगा, जो कि अनुचित होगा।

सामान्य तौर पर, जी–20 अपने रिकॉर्ड को बनाए रखने में स्थिर नहीं रहा है। सितंबर 2022 में प्रकाशित जी–20 रिसर्च ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2021 से जून 2022 तक की अवधि की समीक्षा करते हुए यह दर्ज किया गया है कि जी–20 सदस्यों ने 2021 रोम शिखर सम्मेलन में किए गए 21 प्राथमिकता प्रतिबद्धताओं पर 68% अनुपालन दर का प्रबंधन किया। यह रिकॉर्ड 2020 में आयोजित रियाद शिखर सम्मेलन में किए गए 20 प्रतिबद्धताओं पर 85% की अनुपालन दर से बहुत कम था। रिपोर्ट में प्राथमिकता प्रतिबद्धताओं के बीच विजेता और कमजोर क्षेत्रों का उल्लेख किया गया था: समावेशी वसूली पर विकास प्रतिबद्धता उच्चतम अंतरिम अनुपालन 93% थी। इसके बाद जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय सहयोग की प्रतिबद्धता, कुपोषण के लिए खाद्य और कृषि प्रतिबद्धता और स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्धता अनुपालन 90% था। सार्वजनिक–निजी भागीदारी में संरचना की प्रतिबद्धता अनुपालन 88% और स्थानीय मुद्रा बाजारों पर दो मैक्रोइकॉनॉमिक्स प्रतिबद्धता अनुपालन 83% दर्ज किया गया। कच्चे कोयले से ऊर्जा प्रतिबद्धता का अनुपालन सबसे कम 30% दर्ज किया गया था। जी–20 सदस्यों द्वारा अंतरिम अनुपालन दर के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम में 90% पर उच्चतम अनुपालन था, इसके बाद जर्मनी में 88% था और जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूरोपीय संघ में 81% अनुपालन दर्ज किया गया। इंडोनेशिया, जो 2022 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था, अनुपालन के लिए 55% से 18वें स्थान पर था। रूस और दक्षिण अफ्रीका में सबसे कम 50% अनुपालन था। (3)

विभिन्न देशों की विभिन्न प्रतिबद्धताओं पर अनुपालन दरों में ये अंतर जी–20 की समन्वय विफलताओं को दर्शाता है। हालांकि, ये समूह की मुख्य चुनौती नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये चुनौतियां मुख्या समस्याओं से निपटने में जी 20 का ध्यान भंग करने की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, जी 20 सदस्य

भी अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति वास्तविक नहीं है। वे कुछ प्रतिबद्धताओं पर सहमत होते हैं, जो पहले से ही उनके राष्ट्रीय एजेंडे में होती है। यह हमें फिर से उसी बिंदु पर वापस ले आता है कि सदस्य केवल तभी जी20 के सुझावों से सहमत होंगे, यदि वे उनके अपने राष्ट्रीय हित में होंगे। इसके अलावा, जी 20 ने सदस्य देशों के अनुपालन के लिए बाध्य उपकरण और नियंत्रण ढांचे को स्थापित नहीं किया है। इसी कारण जी 20 कार्रवाई को बाध्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह केवल अपने सदस्यों के कार्यों की समीक्षा, जांच और नियंत्रण कर सकता है, और उन देशों पर दबाव बना सकता है, जो जी 20 और अन्य सदस्य देशो की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। जी–20 में बाध्यता मानदंडों की शुरूआत के बारे में सुझाव दिए गए थे, किन्तु ऐसा करने से यह सदस्यों को नीतिगत चर्चा में शामिल होने से दूर कर सकता है यदि जी–20 द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का अनुपालन अनिवार्य हो जाता है।

संक्षेप में, जी–20 को भी निर्णय लेने से पहले अपनी कमजोरियों और सीमाओं से परिचित होना चाहिए। अधूरे लक्ष्यों और पहुंच में विफलता, जी 20 की प्रभावी मंच के रूप में छवि को धूमिल करता है और इसके अस्तित्व को खतरे में डालता है। जी 20 को संचालन समिति के रूप में अपनी भूमिका का पालन करना चाहिए और विश्व संचालन की कामना का त्याग करना चाहिए। (4)

जी 20 के वर्षों के प्रदर्शन का आकलन

जी 20 की स्थापना के बाद से इसके प्रदर्शन को समझने के लिए इसे दो अलग–अलग कार्यक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला भाग ''विशिष्ट वर्ग के लिए एक मंच'' होना है। जी 20 को वित्तीय संकट का मुकाबला करने के लिए और विश्व अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 'मंत्री स्तर के मंच' के रूप में शुरू किया गया था। विशाल निजी क्षेत्र के हितधारकों को स्थिरता प्रदान करके तथा बहाली में बढ़ोतरी करके एक प्रेरक के रूप में मुद्रा उपायों का उपयोग करने के अपने लक्ष्य को जी 20 ने बखूबी प्राप्त किया।

जी 20 अर्थव्यवस्थाओं के इन प्रारंभिक प्रयासों ने, आर्थिक क्षेत्र से दूर, एक विश्व रक्षक के रूप में कार्य किया। परन्तु अफसोस की बात यह है कि एक बार प्राथमिक लक्ष्य पूरा हो जाने के बाद, इसका केंद्र मुख्या लक्ष्य से हटकर सदस्य देशों के व्यक्तिगत राष्ट्रीय हितों की ओर भटक गया। शीर्ष स्तर पर सम्पूर्ण एकता बनाए रखने के बाद भी, मध्यम और निम्न वर्ग अभी भी संकट में है। बेरोजगारी, न्यूनतम मजदूरी में गिरावट, आय में देरी आदि इन वर्गों पर संकट के कुछ प्रभाव है।

परिणामस्वरूप, अगले कुछ वर्षों के दौरान, कई सदस्य राज्यों ने बेरोजगारी को दूर करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई। जिन प्रतिबद्धताओं पर सहमति हुई, उनमें उपलब्ध नौकरियों की संख्या में वृद्धि, उच्च न्यूनतम मजदूरी और श्रम हिस्सेदारी में वृद्धि शामिल थी। वित्त ट्रैक के अलावा, रोजगार पर कार्यकारी समूह के साथ श्रम मंत्रियों का नियंत्रण स्थापित किया गया, जिसके बाद 2015 में श्रम आय हिस्सेदारी पर एक उपसमूह बनाया गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि नीति में बदलाव के लिए जी 20 द्वारा दिए गए सुझावों को कभी शामिल नहीं किया गया। वे लागू किये बिना केवल शब्द ही रह गए !

बेरोजगारी और आय के नुकसान की व्यापक समस्या से निपटने के लिए जी 20 में गंभीरता की कमी के परिणामस्वरूप राजनीतिक मुद्दों पर प्रभाव दिखाई देने लगे। यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से बाहर हो गया, ट्रम्प सत्ता में आए ये ऐसे कुछ उदाहरण थे। जी–20 को विशिष्ट वर्ग द्वारा अपना कार्य सिद्ध करने वाले तंत्र के रूप में देखा जाने लगा। किन्तु यदि जी–20 ने घटती मजदूरी दर की समस्या के समाधान और समन्वय के अवसरों को गंवाया नहीं होता, तो वैश्वीकरण के प्रभाव श्रमिक वर्ग पर कम हो सकते थे। जी–20 संपन्न वर्ग में बढ़ती षेयरों की गति को रोक या धीमा कर सकता था।

दूसरा कार्यक्षेत्र सदस्य राज्यों में तालमेल बनाना था। 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार में बदलाव के बाद से जी–20 सदस्य देशो के व्यक्तिगत हितों ने इसके संयुक्त लक्ष्यों का उन्मूलन कर दिया। सदस्य देशो के हित एक सीमा तक ही मेल खाते थे, जहां वैश्विक चुनौतियों को हल करने में जी–20

की आवश्यकता थी। राष्ट्रों ने कुछ सामान्य हितों को साझा किया, कुछ मुद्दों को सामान रूप से हल किया गया, उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और विकास, असमानता और श्रम भागीदारी इत्यादि। हालाँकि, समय के साथ, जैसे–जैसे सरकारें बदलीं, उनकी रुचियाँ भी बदलीं और बाद में कार्रवाई भी बदल गई।

2016 के बाद से जी–20 के भीतर एक नया चलन उभरा, जिसमें कई गुटों का विकास देखा गया। चीन और रूस के विकास को रोकने की विभिन्न रणनीतियाँ बन रही थीं, जिसने इस प्रवृत्ति को जन्म दिया। छोटी अर्थव्यवस्थाओं ने भी पक्षपात करना शुरू कर दिया और ऐसे समूह के साथ गुट बनाने लगे जो भविष्य में उनके एजेंडे के लिए फायदेमंद और सहायक सिद्ध होगा। इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य के परिणामस्वरूप, जी 20 देशो के भीतर समन्वय सुनिश्चित करने और विश्व स्तर पर बेहतर भविष्य के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल होने लगा। (5) हाल के यूक्रेन–रूस युद्ध ने भी गुटों और पक्षपात के विकास को तेज कर दिया। संक्षेप में, पिछले कुछ वर्षों में जी 20, गुटों में विभाजित होकर दुनिया का एक प्रतिबिंब बनकर रह गया। (5)

ब्रिक्स का विश्लेषण

नवंबर 2021 में, ब्रिक्स ने अपने शानदार 20 साल पूरे किए, क्योंकि यह शब्द पहली बार गढ़ा गया था। इसने सदस्य देशों के बीच 15 साल के सहयोग और सामंजस्य को भी अंकित किया। अब समीक्षा करने का समय है कि क्या इस मंच ने वास्तव में अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया है या यह अपने मार्ग से भटक गया है।

ब्रिक शब्द विश्व स्तर पर परिवर्तित शक्ति योजना के प्रतिनिधित्व के रूप में सामने आया। यह माना गया कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन विश्व अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डालेंगे और इस वैश्विक पुनरुत्थान के दौरान बाकी दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे। अर्थशास्त्रियों ने इन उभरती शक्तियों की क्षमता और इन देशों में व्यापार और निवेश के विस्तार की संभावना को महसूस किया था। परिणामस्वरूप, ब्रिक्स अन्य देशो में चर्चा का विषय बन गया !

यह माना गया कि यह समूह दुनिया का रूप बदल सकता है, क्योंकि वे सामूहिक रूप से दुनिया की आबादी का लगभग 50% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक चौथाई हिस्सा हैं। इस मंच पर विश्वास करने का एक और कारण भी था, क्योंकि उन्होंने 2008 में दक्षिण अफ्रीका को इस रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया और आज विख्यात ब्रिक्स नाम से जाना जाता है।

हालांकि, जिम ओ'नील, जिन्होंने इस संक्षिप्त नाम की संरचना की, उनके अनुसार यह समूह पूरी तरह से आशाओ पर खरा नहीं उतर पाया है। चीन और भारत को छोड़कर बाकी देशों ने तो और भी खराब प्रदर्शन किया है। चीन एक अग्रणी अर्थव्यवस्था और विनिर्माण का केंद्र बन गया है और भारत ने भी आज वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है जिसकी कल्पना बीस साल पहले की गई थी। ये दोनों देश विश्व अर्थव्यवस्था और समग्र विकास योगदान में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

हालाँकि, भारत को 2014 के बाद से कुछ असफलताये भी मिली है। अचानक हुए विमुद्रीकरण, जिसने सबसे कमजोर लोगों को इस तरह से प्रभावित किया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। नौकरियों का नुकसान, पर्याप्त रोजगार पैदा करने में विफलता, आय की हानि, न्यूनतम मजदूरी में गिरावट, इन्ही असफलताओ में से कुछ है।

कोविड –19 ने संकट का विस्तार करके पूरी दुनिया को प्रभावित किया और गरीबी रेखा से नीचे की एक बड़ी आबादी को खत्म कर दिया।

इस प्रकार, सबसे कम अंक वाले देशो ने शुरू में अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि, बाद के वर्षों में उनकी प्रगति कम हो गई। विश्व जीडीपी में उनका वर्तमान योगदान वही है जो शुरुआत में था। इसका कारण आयात और घरेलू खपत के लिए अन्य देशों पर उनकी अत्यधिक निर्भरता हो सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य एक अन्य जरुरी बात यह है कि वैश्विक विकास के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदस्यों के बीच में समन्वय की कमी थी। (6)

ब्रिक्स को मूल रूप से राजनीतिक, आर्थिक, सामुदायिक और शैक्षणिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था।

1. राजनीतिक सहयोगः

ब्रिक्स के राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग का उद्देश्य अधिक न्यायसंगत और निश्पक्ष दुनिया के लिए षांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग प्राप्त करना था। ब्रिक्स ने वैश्विक राजनीतिक संरचना को और अधिक स्थिर बनाने के लिए नीतिगत ढांचे पर विचार विमर्श करने और एक–दूसरे की उपलब्धियों और गलतियों से सीखने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य किया। ब्रिक्स ने अफ्रीकी देशों के लिए दक्षिण–दक्षिण सहयोग के एजेंडे को आगे बढ़ाने और उत्तर–दक्षिण वार्ता को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र के रूप में भी काम किया। इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों को उनकी गतिविधियों में शामिल करके प्रक्रिया को समावेशी बनाना था।

2. आर्थिक सहयोगः

ब्रिक्स देशों के बीच बढ़ती व्यापार प्रथाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग गतिविधियों को बढ़ावा दिया। आर्थिक और व्यापार सहयोग के क्षेत्रों में समझौते किए गएय नवाचार सहयोग, सीमा शुल्क सहयोगय ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल, कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच रणनीतिक सहयोग आदि। इन गतिविधियों ने आर्थिक सहयोग को मजबूत किया और सीमा पार व्यापार तथा बाजारों को बढ़ावा दिया। जिसने साझा उद्देश्यों की भावना को मजबूत बनाने में भी मदद की। ब्रिक्स सहयोग के दौरान एकीकृत भुगतान प्रणाली के लिए 'ब्रिक्स' क्रिप्टोकरंसी का प्रस्ताव पेश किया गया, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

3. सामुदायिक सहयोगः

संस्कृति, खेल, शिक्षा, फिल्म और युवाओं के लिए समुदायों के बीच सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। व्यक्तिगत आदान–प्रदान को आवश्यक माना गया क्योंकि वे मित्रता को बढ़ावा देते हैं, पुरानी साझेदारी को गहरा करते हैं और ब्रिक्स देशों के बीच समझ को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह के व्यक्तिगत आदान–प्रदान में युवा राजनयिक मंच, संसदीय मंच, ट्रेड यूनियन मंच, सिविल ब्रिक्स तथा मीडिया मंच भी शामिल हैं।

4. शैक्षणिक सहयोगः

सदस्य देशों में छात्र विनिमय कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसमें अन्य देशों के छात्र शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन कर सकते थे। ब्रिक्स देशों के बीच एकता का माहौल विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का भी उद्घाटन किया गया, जिससे प्रत्येक देश के लाखों बच्चे भाग ले सकें।

इस प्रकार अब तक ब्रिक्स ने कुछ प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं। औपचारिक रूप से इस मंच का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्त संरचना में सुधार लाना और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना था। दुर्भाग्यवश वे अभी भी पुराने तंत्र और शक्ति के वितरण का अनुसरण करते हैं। हालाँकि, सदस्य देशों की सहमति और प्राथमिकताओं में अंतर के कारण ब्रिक्स को बहुत अविश्वास का सामना करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स देशों में सहयोग का विस्तार वित्त के लिए हुआ और इसमें शिक्षा, व्यापार और विकास, वैश्विक स्वास्थ्य, सुरक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों की एक श्रृंखला भी शामिल थी।

यह मंच अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थानों में आवश्यक सुधार लाने में सफल रहा, जैसे कि वह विश्व अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने तथा बढ़ते व्यापार और वित्तीय बाजारों को विनियमित करने के लिए प्रभावित करता हैं।

न्यू डेवलपमेंट बैंक

ब्रिक्स की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की स्थापना थी, जो ब्रिक्स सदस्यों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जो संयुक्त रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद को 24% और विश्व व्यापार को 16% का योगदान प्रदान करता है। ऐसी संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पहली बार 2012 में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रखा गया था। हालांकि, 2014 में फोर्टालेजा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, इसने अंततः 2015 में अपना संचालन शुरू किया।

एनडीबी का उद्देश्य वैश्विक विकास और बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के विकास प्रयासों के लिए ब्रिक्स सदस्यों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों में संरचना और दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों के लिए संसाधनों को नियोजित करना है। बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन और क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में है। एनडीबी ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्श तंत्र पर कार्य करता है जिसमें सभी सदस्य देशों को समान अधिकार प्राप्त हैं। एनडीबी ने अब तक 70 संरचनाये और दीर्घकालीन विकास परियोजनाओं को 25.07 बिलियन अमरीकी डालर (एनडीबी आपातकाल ऋण सहित) प्रदान किया है। पिछले पांच वर्षों में सभी सदस्य देशों में सहायता सुविधा) प्रदान की गई है। जिसमें भारत की 6.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 18 परियोजनाएं शामिल हैं। एनडीबी स्थायी संरचना, शुद्ध ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, स्वच्छता, बाढ़ संरक्षण, नवीकरण और हरित ऊर्जा, परिवहन, बुनियादी ढांचे, सिंचाई, कृषि और स्मार्ट षहरों जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को निधि प्रदान करता है। (7)

कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट

ब्रिक्स सदस्य देशों द्वारा 2015 में एनडीबी के साथ स्थापित सीआरए ने भुगतान दबावों के वास्तविक अथवा संभावित अल्पकालीन संतुलन के विरुद्ध नगदी और सतर्क तंत्रो के माध्यम से सहयोग स्थापना के लिए एक रूपरेखा निर्धारित की। यह दुनिया भर में बढ़ते वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया था। सीआरए के लिए प्रारंभिक निवेश एक मिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसका उद्देश्य वैश्विक वित्त संरचना की रक्षा करना भी था।

ब्रिक्स राष्ट्रों की प्रगति के मार्ग में कई चुनौतियाँ पाई गई है। सदस्यों के बीच मतभेद, आर्थिक असंतुलन, देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद, इनकी शीर्ष चुनौतियों में से है। इसके अलावा यह मंच केवल वर्तमान सदस्यों का प्रभुत्व ही प्रदर्शित करता है। जिनके बढ़ते बाजारों की शक्ति ब्रिक्स के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। आर्थिक स्थिरता की दिशा में विश्वव्यापी नजरिया सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

प्रासंगिक बने रहने के लिए ब्रिक्स को अपना दायरा और एजेंडा बढ़ाना होगा। उसे समूह के भीतर अन्य देशों को शामिल करना होगा। सभी सदस्य देशो की राजनीतिक संरचनाओं की प्रकृति भिन्न हैं। ब्राजील एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जबकि रूस तानाशाही का पालन करता है।

बीस साल पूरे करने पर ब्रिक्स के मूल सिद्धांतों का उसके पांचो सदस्यों के संबंध में मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्योंकि वे अपने स्वयं के व्यक्तिगत एजेंडे का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार के व्यक्तिगत एवं स्वतंत्र हित पांचो देशों, विशेष रूप से भारत और चीन के बीच गंभीर संघर्ष की स्थिति का कारण बन सकते हैं।

अपने मार्ग में ब्रिक्स ने असफलताओं का भी सामना किया है। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार के कार्य को पूरा नहीं कर पाया। पृथक दृष्टिकोण और अन्य देशों, मुख्य रूप से अमेरिका के साथ सहयोग समझौतों पर विफलता के परिणामस्वरूप यह मंच अपना विस्तार नहीं कर पाया। कुछ सदस्य देशों ने यूक्रेन–रूस युद्ध के परिणामस्वरूप मंदी का अनुभव किया तथा रूस को बाकी देशों से अलग कर दिया। कोविड–19 के परिणामस्वरूप, ब्रिक्स के सभी सदस्य विकास की अपनी गति को बनाए रखने में बुरी तरह विफल रहे और उनका विकास स्तर दस साल पीछे चला गया।

चूंकि चीन ब्रिक्स के कुल निर्यात का लगभग 38% योगदान देता है, इसलिए इसे हमेशा ब्रिक्स के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में हावी देखा गया है। अराजकता और नीतिगत समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप वर्षों से भारत और चीन के बीच संबंध कमजोर रहे हैं।

भविष्य कैसा होगा?

जैसा कि सोचा गया था, जी 20 और ब्रिक्स दोनों समूहों के प्रारंभिक वर्ष संतोषजनक थे और सदस्य देश प्राथमिकता के सामान्य मुद्दों पर सहयोगात्मक रूप से काम करने में सक्षम थे। हालांकि, हाल के वर्षों में, मंचों ने प्रभावी रूप से कार्य करने और अपने उद्देश्य के प्रति सजग बने रहने के लिए संघर्ष किया है। आने वाले वर्षों में इन मंचो के प्रासंगिक बने रहने के लिए, सभी सदस्य देशों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे पीछे मुड़कर देखें और छूटे हुए अवसरों का विश्लेषण करें, जो अब भी उपलब्ध हैं, और इन मंचों को उनकी सीमाओं से दूर करने का प्रयास न करें। समूहों को अपने दृष्टिकोण और कामकाज में संशोधन करने और वापस अपने शुरुआती दौर में जाने की आवश्यकता है। उन्हें इस तथ्य के साथ तालमेल बिठाना होगा कि दुनिया में कई शक्ति केंद्र हैं और सभी सदस्य देशों को निर्णय में योगदान देने के लिए समान मंच प्रदान करे।

विकास चुनौतियों के बेहतर समाधान के लिए एक अतिरिक्त शोध विभाग की स्थापना जी 20 और ब्रिक्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। मंचों को बदलते परिवेश के अनुसार अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। उन्हें पैरिश समझौते और अन्य दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करके प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

ब्रिक्स के संबंध में, एनडीबी तथा अन्य विश्व स्तर वित्त संस्थानों के साथ मिलकर दीर्घकालीन विकास की गतिविधियों का वित्तपोषण किया जाना चाहिए। डिजिटलीकरण, प्रौद्योगिकी, औद्योगीकरण, नवाचार, व्यापार तथा निवेश सहयोग के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्रों, अनुसंधान केंद्रों आदि की स्थापना और संचालन करना चाहिए। पूर्व स्थापित ब्रिक्स महिला गठबंधन को बढ़ावा देना चाहिए और ब्रिक्स में महिला सशक्तिकरण के रूप में इसका उपयोग करना चाहिए। देश में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए। (8)

सभी ब्रिक्स देश जी 20 में शामिल होने के बावजूद भी, प्रमुख वैश्विक मंचो में लिए गए निर्णय चीन, भारत सहित विशाल अर्थव्यवस्थाओं को अधिक प्रभावित करते है, किन्तु अन्य देशो पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मतदान प्रणाली में सुधार होने से कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को भी अपनी आवाज उठाने और अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। परिणामस्वरूप, चीन, ब्राजील और भारत को बड़े पैमाने पर फायदा हुआ है। हालाँकि, दक्षिण अफ्रीका की

बोर्ड में तीसरी सीट के लिए दी गई अपील को खारिज कर दिया गया। इसलिए, दक्षिणी देशों को भी निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने और उत्तर–दक्षिण सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए।

ब्रिक्स देश जी 20 मंच में भी शामिल हैं और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नियमों को विकसित करने का एक हिस्सा हैं। किन्तु जी 20 एजेंडा छोटी अर्थव्यवस्थाओं के हितों का विरोध करते हुए हमेशा अमीर और शक्तिशाली लोगों से प्रभावित रहा है। इस प्रथा को बदलना होगा और सभी सदस्य देशों द्वारा अनुपालन के लिए कुछ नियम विकसित किए जाने चाहिए।

एनडीबी और सीआरए की स्थापना की दुनिया भर के देशों ने काफी सराहना की थी। हालाँकि, इन पहलों में पारदर्शिता और जवाबदेही मानकों का अभाव था। सदस्यों के लिए एनडीबी से जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन था और यह उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध भी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, एनडीबी में यदि किसी उपभोक्ता को नुकसान होता है, तो यहाँ कोई जवाबदेही तंत्र उपलब्ध नहीं है। यह विश्व स्तर के अन्य मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करने के बजाय केवल आर्थिक मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित करते है।

न्यायसंगत वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स को अपने क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसे प्राप्त करने के लिए, सदस्य देशों की सरकारों के मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सबसे पहले, उन्हें अपनी गतिविधियों के प्रत्येक लाभार्थी के अधिकारों की रक्षा करने पर ध्यान देना होगा। इसलिए, परियोजनाओं के नियंत्रण और मूल्यांकन के लिए एक मजबूत प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अलावा जवाबदेही मानकों को भी लागू करना होगा। यदि कोई व्यक्ति इन देशों की किसी गतिविधि से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, तो सदभावना और शांति बनाए रखने के लिए प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए एक तंत्र बनाया जाना चाहिए।

अंत में, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और तीसरे पक्ष के निर्णायक अधिकारियों को प्रस्तावित सुझावों की संबंधता को समझने और उपलब्ध /आवंटित संसाधनों के उचित उपयोग में सक्षम होना चाहिए। यह समूह में विश्वास को पुनः स्थापित करेगा और प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। (9)

हालाँकि इस तरह के समूह का गठन उस समय एक सकारात्मक कदम था, इसकी भूमिका और मूल्यों का मूल्यांकन बहुत अधिक किया गया था। यह मंच सदस्य देशों के हितो और प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करने और साँझा एजेंडा पर सहमती के साधन के रूप में कार्य करता है। चीन अपने नवाचारों के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए मंच का उपयोग करता है, और रूस इसे वित्तीय सहायता के लिए देखता है। (10)

शेष प्रासंगिक

दुनिया का कोई भी देश कोविड–19 महामारी से नहीं बचा। वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों और अर्थव्यवस्थाओं के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी बाधा उत्पन्न हुई। व्यवस्थाओं की कमजोरियाँ उजागर हुई। दुनिया भर में सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आशाओ पर खरा उतरने और महामारी के कठोर प्रभावों को कम करने के लिए ठोस समाधान प्रदान करने में विफल रहे।

इस प्रकार, ब्रिक्स और जी20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए अब यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या हुआ है, वे इसका एहसास करें, आत्म मूल्यांकन करें, और अपनी रणनीतियों और कार्यों पर विचार करें यदि वे प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं। सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए भी यही सच है।

जी20 और ब्रिक्स की स्थापना हुए बीस साल से अधिक हो गए हैं और वे वर्तमान में संकट के प्रभावों से उभरने के लिए जूझ रहे हैं। अन्य संस्थाएँ – जैसे क्वाड, ओकस और अन्य – क्यों बनाई गई? दोनों मंचों में नेतृत्व की कमी थी और वैश्विक संकट के दौरान वे कम एकजुट थे। सदस्य देशों के बीच आम सहमति, समन्वय और सहयोग की भारी कमी थी।

इसलिए, अब समय आ गया है कि दोनों बहुपक्षीय समूहों का जीर्णोद्धार किया जाए। यह अब पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक और अत्यावश्यक हो गया है। उनके मूल मूल्यों से दूर अन्य चुनौतियाँ उन पर दबाव डाल रही हैं: जैसे जलवायु परिवर्तन, डिजिटलीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतर्राष्ट्रीय वित्त और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आदि।

जी 20 और ब्रिक्स, विश्व व्यवस्था का एक प्रतिबिंब हैं, और वर्तमान में इसमें सामंजस्य का अभाव है। इस स्तर का एक संस्थान तभी प्रभावी और प्रासंगिक हो सकता है जब उसके सदस्य आपस में सहमत हों और एक बड़े एजेंडे के लिए मिलकर काम करने को तैयार हों। यहां तक कि सांझी चुनौती कोविड–19 भी इन सदस्यों को एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाई।

संदर्भः

1. https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/G20_Brief_for_website_-_27.10__1___1_.pdf
2. https://icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=2382&lid=1782
3. http://www.g20.utoronto.ca/compliance/2021rome-interim/00-2021-g20-compliance-interim-intro.pdf
4. https://carnegieendowment.org/files/Life_for_G20.pdf
5. https://www.iisd.org/articles/g20-hopes-failures
6. https://www.trtworld.com/magazine/brics-20-years-on-a-success-or-failure-52410
7. https://brics2021.gov.in/ndb
8. https://iasscore.in/current-affairs/mains/brics-achievements-failures-and-future-an-analysis#:~:text=Failure%20of%20BRICS%20to%20sign,economic%20expansion%20of%20BRICS%20countries.
9. https://thewire.in/economy/brics-reform-socio-economic-justice
10. https://www.project-syndicate.org/commentary/brics-20-years-of-disappointment-by-jim-o-neill-2021-09

HEINRICH BÖLL STIFTUNG
INDIA

www.boell.de, www.in.boell.org

हेनरिक बॉल स्टिफतुंग के बारे में

हेनरिक बॉल स्टिफतुंग एक जर्मन संगठन और हरित आंदोलन का हिस्सा है जो दुनिया भर में समाजवाद, उदारवाद और रूढ़िवाद की पारंपरिक राजनीति की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ है। हम एक ग्रीन थिंक–टैंक और एक अंतरराष्ट्रीय नीति नेटवर्क हैं, हमारे मुख्य सिद्धांत पारिस्थितिकी और स्थिरता, लो. कतंत्र और मानवाधिकार, आत्मनिर्णय और न्याय हैं। हम लैंगिक लोकतंत्र पर विशेष जोर देते हैं, जिसका अर्थ है सामाजिक मुक्ति और महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार। हम सांस्कृतिक और जातीय अल्पसंख्यकों के समान अधिकारों के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। अंत में, हम अहिंसा और सक्रिय शांति नीतियों को बढ़ावा देते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, हम उन अन्य लोगों के साथ रणनीतिक साझेदारी चाहते हैं जो हमारे मूल्यों को साझा करते हैं। हमारे उपनाम, हेनरिक बॉल, उन मूल्यों को व्यक्त करते हैं जिनके लिए हम खड़े हैं: स्वतंत्रता की सुरक्षा, नागरिक साहस, सहिष्णुता, खुली बहस, और विचार और कार्रवाई के स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में कला और संस्कृति का मूल्यांकन। हमारा भारत संपर्क कार्यालय 2002 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था।

VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

www.vaniindia.org

वाणी के बारे में

एक मंच के रूप में, वाणी स्वैच्छिकवाद को बढ़ावा देती है और स्वैच्छिक कार्रवाई के लिए जगह बनाती है। एक नेटवर्क के रूप में, यह देश में स्वैच्छिक कार्रवाई के वास्तविक राष्ट्रीय एजेंडे के निर्माण के लिए सामान्य क्षेत्रीय मुद्दों और चिंताओं के अभिसरण को लाने का प्रयास करता है। यह स्वैच्छिक क्षेत्र के विभिन्न प्रयासों और पहलों के लिंकेज को भी सुगम बनाता है।

अस्वीकरण: यह प्रकाशन हेनरिक बॉल स्टिफ्टंग के सहयोग से तैयार किया गया था। प्रकाशन में निहित विचार और विश्लेषण लेखक(कों) के हैं और जरूरी नहीं कि वे फाउंडेशन के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।